IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)
Volume 23, Issue 1, Ver. 9 (January. 2018) 85-87
e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
www.iosrjournals.org

ग्रामीण भारत में खाद्य असुरक्षा और गरीबी के मध्य सम्बंध

डॉ अभय कुमार श्रीवास्तव
अर्थशास्त्र विभाग, एल0बी0एस0 कॉलेज गोंडा

सारांश
जिन राज्यों में खाद्यान्नों का उत्पादन कम होता है वहाँ पर निम्न आय वर्ग कम कैलोरी अन्तर्ग्रहण की समस्या से प्रभावित होता है यद्यपि उस राज्य का औसत उपयोग पर्याप्त होता है। न्यूनतम 5 प्रतिशत जनसंख्या के कैलोरी अन्तर्ग्रहण के साथ–साथ औसत रुप से राज्य में कैलारी अन्तर्ग्रहण प्रति व्यक्ति अनाजों के शुद्ध उत्पादन से महत्वपूर्ण रुप में सम्बंधित है। इसका दो मुख्य कारण है– जो पर्याप्त कैलोरी अन्तर्ग्रहण में सक्षम बनती है, पहला, उत्पादन के क्षेत्रों में कीमते सम्भवतः कम होती है जो गरीबो को पर्याप्त अन्तर्ग्रहण में सक्षम बनती है, दूसरा पर्याप्त जीविका अवसर वाले क्षेत्रों में न्यूनतम व्यय वर्ग की पर्याप्त या अधिक कैलोरी अन्तर्ग्रहण की सम्भावना भी अधिक होती है।

प्रस्तावना

खाद्य पहुँच खाद्यान्नों के खरीदने की क्षमता पर निर्भर करती है जो जीविका पहुँच (Livelhood Acess) से जुड़ा हुआ है। जीविका पहुँच कोई रोजगार नहीं है बल्कि दीर्घ अवधि में आय के निश्चित पहुँच को व्यक्त करता है। जिसका महत्व दीर्घकालीन जीविका पहुँच के द्वारा खाद्य को खरीदने की क्षमता को बढ़ाने में महत्व है। व्यक्ति बिना निर्वहनीय जीविका के गरीब बना रहता हैं। बेरोजगारी की अपेक्षा गरीबी एक बड़ी समस्या है जिसे उत्पादकीय जीविका के माध्यम से मुख्यतः हल किया जा सकता है।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या उन व्यक्तियों को व्यक्त करता है जिसके पास उत्पादकीय जीविका (Productive Livelihood) की पहुँच नहीं है। गरीबी के कारण उनकी खाद्य तक पहुँच कम होती है, जिसके परिणाम स्वरुप उनकी खाद्य असुरक्षा और जोखिम (Vulnerability) भी अधिक होती हैं।

खाद्य असुरक्षा और गरीबी के मध्य सम्बंध काफी जटिल है तथा इसे एक दुष्चक्र (Vicious Cycle) के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि निर्धनता निःसंदेह रूप से भूख का एक कारण है जबकि अपर्याप्त खाद्य तथा उचित पोषण का अभाव स्वयं या अपने आप में गरीबी का एक अन्तर्निहत कारण है। भूख, खाद्य असुरक्षा तथा कुपोषण गरीब लोगों को निर्धनता से बाहर निकलने में रोकते या बाधक है क्योंकि ये सब व्यक्ति के कार्य करने, सीखने तथा अपने पारिवारिक सदस्यों और अपनी देखरेख की क्षमता को कम करते है। लम्बें समय से भूखा व्यक्ति (Chronically Hungry People) गरीबी से बाहर निकालने में सक्षम आवश्यक परिसम्पत्तियों (Necessary Assets) का निर्माण करने मे भी योग्य नही होता है। अतः खाद्य असुरक्षा निम्न प्रकार से गरीबी में वृद्धि करती है–

I. एक व्यक्ति को मूल भूत रूप से कार्य करने तथा उत्पादकीय (Productive) होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा अन्तर्ग्रहण (Sufficient Food Intake) और एक पर्याप्त पोषणीय स्तर की आवश्यकता होती है। कुपोषित व्यक्ति में लगातार कार्य करने की क्षमता नही होती है और इसलिए वह "एक सक्रीय और स्वस्थ जीवन" (An Active and Healthy Life) नही जी सकता है।

II. खराब पोषण (Poor Nutrition) खराब स्कूल प्रदर्शन (Performance) से भी सम्बंधित होता है क्योंकि भूख के कारण बालक निसक्रीय तथा थका हुआ होता है जो इसके सीखने या बौधिक (Cognitive) क्षमता को स्वयं बिगाड़ देती है। इसके परिणामस्वरूप बच्चें स्कूल में खराब प्रदर्शन करते है जिससे उसका भावी आर्थिक पुर्वानुमान या सम्भावनाएं (Prospect) बिगड़ जाती है और इस प्रकार खराब पोषण की प्रवृत्ति निम्न या कम आय से सम्बंधित होती है।

1.1 उद्देश्य और प्रविध (Objective& Methodology)

इस शोध पत्र के विश्लेषण का पहला उद्देश्य यह हैं कि ग्रामीण भारत के जिन राज्यों में गरीबी तथा श्रम आय पर निर्भर जनसंख्या अधिक हैं क्या उन राज्यों में– न्यूनतम व्यय वर्ग(Lower Expenditure Group) में जनसंख्या का ऊर्जा अन्तर्ग्रहण (Calorie Intake) भी कम है या नही।

जबकि दूसरा उद्देश्य ग्रामीण भारत के जिन राज्यों में गरीबी तथा श्रम आय पर निर्भर जनसंख्या अधिक हैं क्या उन राज्यों में–1890 कैलोरी से कम उपभोग करने वालें परिवारों का प्रतिशत भी अधिक हैं की नही।
इस शोध पत्र का विश्लेषण ग्रामीण भारत के मुख्यतः 17 राज्यों के मध्य द्वितीयक आकड़ों पर आधारित हैं जिसके विश्लेषण में मुख्यतः NSSO के आकड़ों का प्रयोग किया गया हैं तथा निष्कर्षो को ARC-View GIS Software के माध्यम से एक मानचित्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया हैं।

1.2 गरीबी का हेड काउंट अनुपात (Head Count Ratio of Poverty)

निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तर पर आधारित है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे 'न्यूनतम स्तर' से नीचे गिर जाय जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएँ विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशो में भिन्न है। अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है।

भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण या आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। खाद्य वस्तुए जैसे– अनाज, दालें, सब्जियाँ, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन है। यदि व्यक्ति इस निर्धारित कैलोरी से कम उपभोग करता हैं तो वह गरीब माना जाता हैं।

		ग्रामीण भारत में आजीविका पहुंच संकेतक			
		1	**2**	**3**	**4**
S.N.	राज्य/भारत	ग्रामीण भारत में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या अनुपात या% आयु जनसंख्या	श्रम बल में प्रति 1000 व्यक्तियों पर दैनिक स्थिति बेरोजगारी दर	सार्वजनिक कार्य के अलावा अन्य आकस्मिक श्रम का औसत दैनिक वेतन (रुपये में)	श्रम आय पर निर्भर परिवार की आयु का प्रतिशत- कृषि मजदूरी और गैर-कृषि मजदूरी / (आयु वर्ग के आकस्मिक श्रमिकों की आयु)
		(2010-11)	(2010-11)		
	India	25.70	57	138.62	34.50
1	Andhra Pradesh	10.96	52	141.53	39.20
2	Assam	33.89	54	135.65	16.90
3	Bihar	34.06	48	125.98	38.20
4	Chhattisgarh	44.61	48	83.85	38.00
5	Gujarat	21.54	29	112.84	32.50
6	Haryana	11.64	46	196.89	25.70
7	Jharkhand	40.84	33	132.04	30.30
8	Karnataka	24.53	34	142.40	35.80
9	Kerala	9.14	169	314.88	37.30
10	M.P.	37.74	33	105.22	33.50
11	Maharashtra	24.22	42	117.36	34.50
12	Orissa	35.69	87	117.43	31.30
13	Punjab	7.66	52	198.64	32.00
14	Rajasthan	16.05	35	159.45	25.40

15	Tamil Nadu	15.83	111	169.93	50.00
16	UttarPradesh	30.4	51	133.06	29.60
17	West Bengal	22.52	83	120.92	46.90

स्रोत: कॉलम-1, योजना आयोग 2010-11, वापस बुलाने की अवधि के आधार पर। कॉलम-2 से 4, -68वां राउंड, एनएसएस रिपोर्ट नंबर 554 भारत में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति 2010-11

योजना आयोग के ग्रामीण भारत में 2011–12 के गरीबी के आकड़ों से स्पष्ट हैं कि ग्रामीण भारत में राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण गरीबी 25.7 प्रतिशत हैं जबकि राज्यों में सबसे अधिक गरीबी छत्तीसगढ़ राज्य में 44.61 प्रतिशत हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के बाद सबसे अधिक गरीबी क्रमशः झारखण्ड (40.84 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (37.34 प्रतिशत), उड़ीसा (35.69 प्रतिशत), बिहार (34.06 प्रतिशत), असम (33.89 प्रतिशत) तथा उत्तर प्रदेश राज्य में 30.4 प्रतिशत गरीबी हैं। इसके विपरीत सबसे कम गरीबी पंजाब, केरल, आन्ध्र प्रदेश तथा हरियाणा राज्य में क्रमशः 7.66, 10.96 तथा 11.64 प्रतिशत गरीबी हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में गरीबी 15 से 25 प्रतिशत गरीबी हैं।

गरीबी का हेड काउंट अनुपात आपदा तथा खाद्य असुरक्षा का सामना करने के लिए व्यक्ति की क्षमता का एक महत्वपूर्ण माप है। सूखे या आकाल के दौरान खाद्यान्न की कमी के समय संतुलित आहार लेने की क्षमता, स्वास्थ्य सहायता प्राप्त करना और अपने को स्वस्थ रखना जैसे अनेक कार्य गरीबी के साथ किये जाते है। राज्यों द्वारा सब्सिडी (सहायकी) प्राप्त खाद्यान्नों, स्वच्छ पीने का पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं, और फ्री शिक्षा के द्वारा आय हस्तान्तरण से वास्तविक आय में सुधार होता है और इस प्रकार गरीबी आय से महत्वपूर्ण रुप से सम्बंधित होती है। वास्तव में NSSOके आकड़े इस पर बल देते है कि निम्न व्यय वर्ग का कैलोरी अन्तर्ग्रहण उच्च व्यय वर्ग के कैलोरी अन्तर्ग्रहण से काफी कम है तथा यह स्पष्ट है कि न्यूनतम उपभोग व्यय वर्ग का कैलोरी अन्तर्ग्रहण अन्य की अपेक्षा ज्यादा कम है।

विभिन्न राज्यों में गरीबी के स्तर के विश्लेषण से स्पष्ट है कि जिन राज्यों में कृषि में विविधता है उन राज्यों में गरीबी भी सापेक्षिक रूप में कम है क्योंकि कृषि में विविधिकरण से कृषि श्रमिकों को अधिक रोजगार प्राप्त होता है। जिन राज्यों में गरीबी 22 प्रतिशत से कम अर्थात राष्ट्रीय औसत ग्रामीण गरीबी से कम है उन राज्यों में गैर–आनाज फसल तथा पशु उत्पादन अधिक है जैसे पंजाब, हरियाणा, केरल, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान तथा गुजरात राज्यों में अनाजों के अलावा दूध, दालें, फल, सब्जियां तथा मत्स्य उत्पादन की ओर अन्य राज्यों के अपेक्षा ज्यादा विविधिकरण है।

निष्कर्ष एवं सुझाव (Conclusion and Suggestion):-

इस प्रकार यह विश्वास योग्य है जिन राज्यों में खाद्यान्नों का उत्पादन कम होता है वहाँ पर निम्न आय वर्ग कम कैलोरी अन्तर्ग्रहण की समस्या से प्रभावित होता है यद्यपि उस राज्य का औसत उपयोग पर्याप्त होता है। न्यूनतम 5 प्रतिशत जनसंख्या के कैलोरी अन्तर्ग्रहण के साथ–साथ औसत रुप से राज्य में कैलारी अन्तर्ग्रहण प्रति व्यक्ति अनाजों के शुद्ध उत्पादन से महत्वपूर्ण रुप में सम्बंधित है। इसका दो मुख्य कारण है– जो पर्याप्त कैलोरी अन्तर्ग्रहण में सक्षम बनती है, पहला, उत्पादन के क्षेत्रों में कीमते सम्भवतः कम होती है जो गरीबो को पर्याप्त अन्तर्ग्रहण में सक्षम बनती है, दूसरा पर्याप्त जीविका अवसर वाले क्षेत्रों में न्यूनतम व्यय वर्ग की पर्याप्त या अधिक कैलोरी अन्तर्ग्रहण की सम्भावना भी अधिक होती है।

Reference:-

[1]. Himanshu (2007): "Recent Trends in Poverty and Inequality: Some Preliminary Results" Economic and Political Weekly, February. 10,

[2]. M. S. Swaminathan Research Foundation & World Food Programme (2002): "Food Insecurity Atlas of Urban India" Printed byTTK Healthcare Limited – Printing Division 328 GST Road, Chormepet Chennai – 600044

[3]. NSSO 68th Round Report NO.555: "Level and Pattern of Consumer Expenditure2010-11", National Statistical Organization, Ministry of Statistics and Programme Implementation Government of India.

[4]. NSSO 68th Round, Report No.554: "Employment & Unemployment Situation in India 2010-11", National Statistical Organization, Ministry of Statistics and Programme Implementation Government of India.

[5]. NSSO 68th Round, Report No.560: "Nutritional Intake of India- 2010-11", National Statistical Organization, Ministry of Statistics and Programme Implementation Government of India.

[6]. Rajuladevi. A. (2001): "Food Poverty and Consumption among Landless Labour Households", Economic and Political Weekly, 35(28), 1659-1667.